



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल, 26, 1985/वैशाख 6, 1907
No. 90] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 1985/VAISAKHA 6, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

सं. 46/2/81-न्याय :—यतः, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक बेंच की स्थापना की मांग से उत्पन्न सभी पहलुओं पर तथा राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने अपने तारीख 4 सितम्बर, 1981 के संकल्प सं. 46/2/81-न्याय के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, श्री जसवंत सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था ;

और, यतः, गोहाटी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मद्रास न्यायालयों को बेंचों के मूल स्थानों से इतर स्थानों पर स्थापित करने और उच्च न्यायालयों के मूल स्थानों के इतर स्थानों पर बेंचों की स्थापना करने के सामान्य प्रश्न के सभी पहलुओं की भी जांच करने और रिपोर्ट देने और इस संबंध में अपनाए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों

और मापदण्डों तथा विशेषकर पूर्वोक्त उच्च न्यायालयों की स्थायी बेंचों की स्थापना की मांगों की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार ने अपने तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के संकल्प सं. 46/2/81- न्याय के तहत भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांगों पर विचार करने के लिए आयोग से कहा गया था ;

और, यतः, आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निर्धारित समय समाप्त हो गया है और आयोग ने समय बढ़ाए जाने की मांग की है ;

इसलिए अब भारत सरकार ने आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का समय अप्रैल, 1985 को 30 तारीख तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाने का निर्णय किया है ।

तदनुसार, आयोग अप्रैल, 1985 की 30 तारीख को या इससे पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

मुरेन्द्र सिंह, उप-सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th April, 1985

No. 46/2/81-Jus.—Whereas the Government of India vide its Resolution No. 46/2/81-Jus., dated the 4th September, 1981 had set up a Commission with Shri Jaswant Singh, Retired Judge, Supreme Court of India as Chairman to consider all aspects arising out of the demand for the constitution of a Bench of the Allahabad High Court for the Western districts of Uttar Pradesh and the various aspects of the recommendations made by the State Government;

And, whereas, the Government of India vide its Resolution No. 46/2/81-Jus., dated the 14th December, 1983 required the Commission to consider the demands made by the State Governments concerned for the establishment of Benches of the High Courts of Gauhati, Karnataka, Madhya Pradesh and Madras at place other than their principal seats and

also to examine and report on all aspects of the general question of having Benches of High Courts at places other than their principal seats and on the broad principles and criteria to be followed in this regard and in particular on the demands for the establishment of the permanent Benches of the High Courts aforesaid;

And whereas the time fixed for submission of the report by the Commission has expired and the Commission has asked for extension of time;

Now, therefore, the Government of India have resolved to extend the time for submission of its report by the Commission upto and inclusive of the 30th day of April, 1985.

2. The Commission will accordingly submit its report on or before the 30th day of April, 1985.

SURENDRA SINGH, Dy. Secy.